भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 234

दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात हब योजना–2024

234. श्री राजेश वर्माः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती शांभवीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 में निर्यात केंन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) योजना के संबंध में वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) योजना के साथ विलय करने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2024 में उक्त योजना के अंतर्गत देश में उत्पादों, निर्यात और आर्थिक कार्यकलापों में हुई वृद्धि के आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के संबधं में ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2024 के दौराना उक्त योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) डीजीएफटी की निर्यात हब के रूप में जिले पहल के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है ताकि जिलों से चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं की निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाया जा सके ताकि उनके स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक लाभों का लाभ उठाया जा सके। राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत, 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है, जिसमे आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अवरोधों का विवरण दिया गया है और चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित उपायों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी वैश्विक बाजारों में सफल होने के लिए व्यवसायों, एमएसएमई और छोटे पैमाने के निर्यातकों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण करने और सहायता प्रदान करने के लिए ई–कामर्स भागीदारों, सरकारी हितधारकों और उद्योग संघो के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

दिसंबर 2022 में, जिला स्तर पर निर्यातकों और विनिर्माताओं के लिए सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) को डीईएच पहल के साथ विलय कर दिया गया था। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से डीजीएफटी निर्यात संवेदीकरण

और संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ और जिलों के साथ कार्य कर रहा है। ये कार्यशालाएं वैश्विक व्यापार को नेविगेट करने के लिए हितधारकों को आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके अलावा, भारत के भीतर और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर ओडीओपी और निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं की दृश्यता को बढ़ावा देने और वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यकलापों को शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ जुड़ाव, वर्चुअल क्रेता–विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है।

(ग) और (घ) यह स्पष्ट किया जाता है कि डीईएच एक पहल के रूप में चल रहा है और आज तक यह कोई स्कीम नहीं है। अतः इस स्कीम के अंतर्गत उत्पादों के निर्यात, रोजगार सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) डीईएच पहल के तहत, भारत के सभी जिलों में निर्यात संवर्धन उपायों को लागू किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 734 जिलो में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है और 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) तैयार की गई हैं। इन पहलों के अंतर्गत चिन्हित किए गए निर्यात क्षमता वाले जिला–वार उत्पादों/सेवाओं की सूची (www.dgft.gov.in/CP/) पर उपलब्ध है।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 9 में, भारत से सीमापार ई–कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके आलोक में, डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी पहल के तहत पहचाने गए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'निर्यात हब के रूप में जिलों के तहत 'आउटरीच' कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2024 में, ई–कामर्स भागीदारों के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप फरीदाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना, जोधपुर, बैंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुम्बई, जमशेदपुर और वाराणसी में मार्च से जून के दौरान 10 जिला निर्यात आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आउटरीच कार्यक्रमों का दूसरा चरण अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच हावड़ा, जयपुर, हरिद्वार, कानपुर नगर, मदुरै, मिर्जापुर, राजकोट बालासोर, जालंधर, आगरा और मेरठ में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

*****